

12.01.2016

**माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी का मसौदा भाषण-**  
**बिहार में नारियल विकास बोर्ड की उपलब्धियाँ**

- नारियल फसल की उपयोगिता, महत्व एवं मांग को देखते हुए कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नारियल विकास बोर्ड की स्थापना 12 जनवरी, 1981 को की गई। आज 37वें स्थापना दिवस के अवसर पर नारियल विकास बोर्ड के 'किसान प्रशिक्षण केन्द्र एवं क्षेत्रीय कार्यालय भवन' का पटना (बिहार) में शिलान्यास किया जा रहा है।
- भारत नारियल के उत्पादन और उत्पादकता में विश्व में अग्रणी देश है। देश में 16 राज्यों और तीन संघ शासित क्षेत्रों में 21.4 लाख हेक्टर क्षेत्र में नारियल की खेती की जाती है। नारियल की खेती, प्रसंस्करण, विपणन और व्यापार संबंधी गतिविधियों से एक करोड़ से अधिक परिवार अपनी आजीविका चलाते हैं। बोर्ड 12 जनवरी 1981 को अस्तित्व में आया जो भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है और इसका मुख्यालय केरल के कोच्चि में है।
- बिहार राज्य में 14,900 हेक्टर में नारियल की खेती होती है और नारियल का उत्पादन 14.138 करोड़ है। वर्ष 1987 में पटना में नारियल विकास बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय और मधेपुरा में प्रदर्शन-सह-बीज उत्पादन फार्म की स्थापना की गई। पटना क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन राज्य केंद्र, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ओड़िशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, असम और प्रदर्शन सह बीज उत्पादन फार्म, मधेपुरा, अभयपुरी, पित्तापल्ली और कोंडागाँव कार्यरत थे। वर्ष 2003 में पटना में राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा की एक हेक्टेयर ज़मीन का आवंटन नारियल विकास बोर्ड को औपचारिक पत्र द्वारा किया। किन्तु वर्ष 2009 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर नारियल विकास बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय पटना, बिहार से गुवाहटी, असम में अंतरित कर दिया गया। मोदी सरकार बनने के बाद बिहार की नारियल उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखते हुए हमने एक केन्द्रीय टीम गठित की। इस टीम ने राज्य केंद्र, पटना के स्थान पर पटना में बोर्ड का नया एवं चौथा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की संस्तुति की जिस पर नारियल विकास बोर्ड ने दिनांक 30.01.2015 को संपन्न 119 वीं बोर्ड बैठक में सहमति व्यक्त की।

- उत्तर बिहार का कोसी क्षेत्र जिसमें कोसी नदी के दोनों तरफ के इलाके आते हैं, नारियल की खेती के लिए उपयुक्त है। अनुमानित है कि बिहार में विशेषकर उत्तर बिहार में तकरीबन 50000 हेक्टर क्षेत्र में सिंचित स्थिति में नारियल की खेती की जा सकती है।

नारियल विकास बोर्ड का लक्ष्य है कि नारियल किसानों को नारियल के उत्पादन, प्रक्रमण, विपणन और नारियल एवं मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात में सहायता देकर भारत को नारियल के उत्पादन, उत्पादकता, प्रसंस्करण एवं निर्यात में अग्रणी बनाना। बिहार नारियल की खेती के गैर पारंपरिक क्षेत्रों में आता है और राज्य में नारियल क्षेत्र के विकास को बोर्ड विशेष ध्यान देता है।

- **किसान प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना**

क्षेत्रीय कार्यालय भवन के निर्माण के साथ ही एक किसान प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की भी पहल की जा रही है। एक हैक्टेयर जमीन में नारियल विकास बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय भवन के निर्माण का शिलान्यास किया गया है। बोर्ड 3.46 करोड़ रुपए की लागत पर निर्माण कार्य के लिए अनुमोदन दे चुका है और राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम को प्रस्तुत कार्य सौंपा गया है। किसान प्रशिक्षण केन्द्र किसानों को कौशल विकास दिलाने के लिए है। यह केन्द्र राज्य में नारियल खेती और उद्योग को मज़बूत बनाने में मदद देंगे।

- बोर्ड ने बिहार राज्य के सिंहेश्वर, मधेपुरा में एक प्रदर्शन सह बीज उत्पादन फार्म स्थापित किया है। फार्म 40 हैक्टेयर क्षेत्र में व्याप्त है जहां एकीकृत कीट/पोषण/रोग प्रबंधन, अंतरा खेती, एकीकृत खेती आदि जैसी विविध वैज्ञानिक नारियल खेती प्रणालियों का निदर्शन किया जाता है।

- प्रदर्शन सह बीज उत्पादन फार्मों में कृषि जलवायु परिस्थितियों के लिए उपयुक्त **गुणवत्तायुक्त पौधों** का उत्पादन किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न किस्मों के कुल 162704 पौधों का उत्पादन बिहार राज्य में किया गया जो बिहार के किसानों को वितरित की गई।

- इस बात को मद्दे नज़र रखते हुए कि भारत के गैर पारंपरिक क्षेत्रों में भी नारियल की खेती का विस्तारण हो रहा है, बोर्ड 'नारियल के अधीन क्षेत्र विस्तार' जैसी योजनाओं के लिए प्राथमिकता दे रहा है। इस योजना के अधीन नारियल के नए रोपण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2014 से लेकर बोर्ड ने अपनी योजना के अन्तर्गत 141.26 हेक्टर क्षेत्र नारियल खेती के अधीन लाया है।

- निदर्शन प्लोटों की स्थापना के लिए योजना (अनुसूचित जाति विशेष कार्यक्रम / जनजाति विशेष कार्यक्रम वर्ग) के अंतर्गत वर्ष 2016-17 के दौरान बिहार में 100 हेक्टर क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रबंधन तरीकों के निदर्शन के लिए 17.5 लाख रुपए का आवंटन नारियल विकास बोर्ड द्वारा किया गया है।
- बोर्ड ग्रामीण इलाकों में संभाव्य रोजगार सृजन पर जोर देता है। इसके लिए फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्री (एफओसीटी) योजना कार्यान्वित की गई जो बेरोजगार युवकों के लिए नारियल ताड़ारोहण, नारियल के खेती कार्य, रोग कीट प्रबंधन आदि पर छह दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यह प्रशिक्षण निःशुल्क है तथा प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण पूरा करने पर ताड़ारोहण यंत्र भी दिए जाते हैं। नाविबो द्वारा ओरिएंटल इन्श्योरेन्स कंपनी के सहयोग के साथ प्रशिक्षणार्थियों को बीमा परिरक्षा भी दी जाती है। एफओसीटी प्रशिक्षणार्थी पर्याप्त रूप से उच्च आय कमा सकते हैं जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आता है।

वर्ष 2014 से लेकर बिहार में कुल 4 बैचों में बोर्ड के कार्यक्रम के अधीन 94 लोगों ने एफओसीटी प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

- बोर्ड विस्तार एवं प्रचार गतिविधियों के भाग स्वरूप राज्य में शिवरात्रि मेला, सिंहेश्वर महोत्सव, एग्री फेयर, किसान मेला, होटी संगम आदि विभिन्न प्रदर्शनियों एवं संगोष्ठियों में भाग ले रहा है। इस के सिलसिले में बिहार राज्य में जनजातीय किसानों को 25000 बीज पौधों का निशुल्क वितरण किया गया। जिसमें कोसी क्षेत्र (रीजन) प्रमुख हैं।

**बिहार में उपरोक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2014 से लेकर कुल 409.06 लाख रुपए नारियल विकास बोर्ड द्वारा मंजूर किए गए हैं।**

अंत में मैं किसानों, उद्यमियों, सरकारी अधिकारियों और नीति निर्माताओं से आह्वान करता हूँ कि बिहार में नारियल क्षेत्र में उपलब्ध संभावी अवसरों का भरपूर लाभ उठाएं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आप सभी ने तहे दिल से समर्थन और सहयोग दिया है जिसकी मैं सराहना करता हूँ। मेरी उम्मीद है कि नारियल किसानों को सहारा देने के लिए आपके द्वारा किए जा रहे जोशीले प्रयासों के फलस्वरूप बिहार राज्य में नारियल के स्वर्णिम युग की शुरुआत ज़रूर होगी।

\*\*\*\*